साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार, 05-11 फरवरी 2024 वर्ष-9, अंक-42
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

इराक, ईरान, दुबई, बहरीन और तुर्की में बढ़ी मांग, चिप्स भी आ रही पसंद, किसानों को मिला अंतरराष्ट्रीय बाजार

» 19 हजार से ज्यादा किसान 23 हजार 650 एकड़ में केले की खेती कर रहे

» सालाना औसतन 16.54 मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा

किसानों के अच्छे दिन, विदेशी बाजार में मध्यप्रदेश के केले ने बनाई पहचान

भोपाल। जागत गांव हमार

अपनी मिठास और ज्यादा दिनों तक खराब नहीं होने के गुणों के कारण बुरहानपुर के केले ने विदेशी बाजार में तेजी से अपनी पहचान बनाई है। खासतौर पर खाड़ी देशों इराक, ईरान, दुबई, बहरीन और तुर्की में यहां के केले की खासी मांग है।

जिले के केला उत्पादक किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलने के कारण उनकी आमदनी भी बढ़ी है। जिले के किसान इससे समृद्ध हो रहे हैं। बुरहानपुर के केले के कारण मध्य प्रदेश भी विदेशों में पहचान बना रहा है। वर्तमान में जिले के 19 हजार से ज्यादा किसान 23 हजार 650 एकड़ में केले की खेती कर रहे हैं। सालाना औसतन 16.54 मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। इसे केंद्र की योजना एक जिला एक उत्पाद में भी शामिल किया गया है। इससे निर्यात के अवसर बढ़े हैं। जिले में मुख्य रूप से जी-9, बसराई, हर्षाली, श्रीमंथी किस्में उगाई जा रही हैं।

केले के चिप्स भी खूब पसंदः यहां बनने वाले केले के चिप्स भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। इसकी सप्लाई देश के कई राज्यों में की जा रही है। वर्तमान में सरकारी मदद से केला चिप्स की तीस से ज्यादा इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। कुछ इकाइयों में केले का पावडर भी तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि बीते दिनों राष्ट्रीय स्तर पर एक जिला एक उत्पाद पुरस्कारों में बुरहानपुर को स्पेशल मेंशन श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है।

दो सीजन से अच्छा मुनाफा

नई तकनीक, सरकारी मदद व मौसम अनुकूल रहने से बीते दो सीजन से अच्छा मुनाफा हो रहा है। बाजार में मांग बढ़ने पर दो से ढाई हजार रुपये प्रति क्विंटल दाम मिले हैं। उन्होंने बताया कि इसकी खेती में प्रति पौधा करीब 140 रुपये लागत आती है। करीब पांच सौ पौधे लगाने पर पांच सौ क्विंटल तक उत्पादन होता है। सीएमवी वायरस जरूर नुकसान पहुंचाता है। यहां का केला दिल्ली और हरियाणा तक जाता है।

पीढ़ियों से कर रहे केले की खेती

जिला मुख्यालय से 16 किमी दूर दापोरा गांव में करीब 60 एकड़ जमीन में खेती करने वाले प्रवीण पाटिल का कहना है कि गांव के अधिकांश किसान पीढ़ियों से केले की खेती करते आ रहे हैं। उन्होंने अपने पिता और दादा से खेती के गुर सीखे। प्रवीण बताते हैं कि पहले इतना मुनाफा नहीं होता था।

अच्छा उत्पादन ले रहे किसान

जिला मुख्यालय से 19 किमी दूर इच्छापुर गांव में भी केला उत्पादक किसानों की संख्या ज्यादा है। करीब 25 एकड़ जमीन में खेती करने वाले किसान राहुल चौहान बचपन से केले की खेती सीख गए थे। 17 सदस्यों के संयुक्त परिवार में रहने वाले राहुल चार भाइयों में सबसे बड़े हैं। लाभ और हानि के बारे में विस्तार से समझाते हुए वे कहते हैं कि यह सब मौसम और बाजार के व्यवहार पर निर्भर करता है। पूर्वजों का मानना था कि ज्यादा पौधे ज्यादा उपज देंगे। प्रति एकड़ डेढ़ लाख से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा होता है। यदि अच्छी तरह से देखभाल हो जाए तो प्रति गुच्छा 30 से 35 किलोग्राम तक का होता है। इसी तरह शाहपुर गांव के राजेंद्र चौधरी भी केले से बेहतर आय ले रहे हैं।

नई व्यवस्थाः किसान अब फोन से भी करें अप्लाई

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन शुरू

भोपाल। मध्यप्रदेश के किसानों को उनकी उपज के वाजिब दाम दिलवाने और उन्हें बिचौलियों एवं दलालों के शोषण से बचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा रबी सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के इंतजाम किए है। विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 5 फरवरी से 1 मार्च तक जिलों की सहकारी समितियों, एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर के साथ ही किसान ऐप के माध्यम से किसानों का पंजीयन कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए किसानों से पंजीयन केन्द्रों में तय की गई समय सीमा में गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराने की अपील जारी की है। खरगोन जिले के खाद्य आपूर्ति अधिकारी भारत सिंह जमरे ने बताया कि समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत कार्यालय, एवं तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र, सहकारी समितियों एवं विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर किसानों का निःशुल्क पंजीयन किया जाएगा। इन केन्द्रों पर किसान सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक पंजीयन करा सकते हैं।

फ्री और सशुल्क पंजीयन

खाद्य अधिकारी के अनुसार किसान घर बैठे भी अपने स्मार्ट एन्ड्रायड मोबाइल के प्ले स्टोर से एमपी किसान एप डाउनलोड कर इस एप के माध्यम से निःशुल्क पंजीयन खुद ही कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि जिनके पास मोबाइल नहीं है, तब ऐसे में वे एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र एवं निजी व्यक्ति यों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर सशुल्क पंजीयन भी करवा सकते हैं।

पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल

पशुपालन मंत्री ने किया केंद्रीय बीज उत्पादन संस्थान का निरीक्षण

प्रयोगशाला में उच्च तकनीक के प्रयोग से मप्र में 90 फीसदी पैदा होंगी बछिया

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय बीज उत्पादन संस्थान भोपाल स्थित सेक्स सोर्टेड वीर्य उत्पादन लैब में की जा रही नवीन तकनीकी के उपयोग से 90 प्रतिशत बछिया पैदा हो रही हैं। प्रयोगशाला में 2 लाख डोज प्रतिवर्ष का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 6.5 लाख डोज का संग्रहण किया जा चुका है। इससे न केवल दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो रही है, अपितु उत्तम नस्ल का गौवंश तैयार हो रहा है। साथ ही भारतीय देशी नस्लों का संरक्षण भी किया जा रहा है। पशुपालन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल ने केंद्रीय बीज उत्पादन संस्थान भोपाल में सेक्स सोर्टेड वीर्य उत्पादन लैब, फ्रोजन सीमन उत्पादन लैब और दुग्ध बुल मदर फार्म का निरीक्षण किया। साथ ही वहां की जा रही विभिन्न गतिविधियों और नवीन प्रयोगों के लिए चिकित्सकों, प्रबंधकों और सभी संबंधितों की सराहना करते हुए उनका हौंसला बढ़ाया।

40 लाख डोज सीमन तैयार | मंत्री को फ्रोजन सीमन उत्पादन लैब के निरीक्षण के दौरान बताया गया कि यहां 14 विभिन्न नस्लों की गाय भैंस के वीर्य का उत्पादन किया जाता है। इसमें अभी तक 38 से 40 लाख डोज सीमन तैयार किए जा चुके हैं। प्रयोगशाला में उच्च अनुवांशिकता गुणवत्ता वाले 200 से अधिक सांड हैं, इनमें जाफराबादी, मुर्रा, साहिवाल, गिर, थारपारकर मालवी, निमाड़ी सांड शामिल हैं।

गिर-साहिवाल के बच्चों को भी देखा

मंत्री ने वहां उत्पादित गिर और साहिवाल के बच्चों को भी देखा। यह सफलतम प्रयोगशाला है जिसमें नस्ल सुधार के अंतर्गत 400 से अधिक वत्स उत्पादित किए जा चुके हैं। मंत्री ने दुग्ध बुल मदर फार्म का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने वहां बहुउद्देशीय देशी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों को संबोधित भी किया।

बायोगैस प्लांट का निरीक्षण

मंत्री ने प्रशिक्षण को स्वरोजगार के साथ ही दुग्ध उत्पादन एवं पशु नस्ल सुधार में उपयोगी बताया। उन्होंने बायोगैस प्लांट का निरीक्षण किया। परिसर में पौधारोपण किया। विभिन्न पशुओं को गुड़ और हरा चारा भी खिलाया। निरीक्षण के दौरान पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के प्रबंध संचालक डॉ. एचबीएस भदोरिया, प्रबंधक डॉ. दीपाली देशपांडे, प्रबंधक डॉ. ए. बनर्जी और प्रगतिशील पशुपालक मौजूद रहे।

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट

गांव चली सरकार

तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य

- आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा
- एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में दी गई मदद
- नौ करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख स्वयं सहायता समूह सशक्त
- आत्मनिर्भर बनने ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिवेश में बदलाव
- नए वित्त वर्ष में पीएम आवास योजना का विस्तार किया जाएगा
- अभी अंतरिम बजट किया गया पेश, चुनाव बाद आएगा पूर्ण बजट
- केंद्र सरकार इस बजट में जनता से जुड़ी योजनाओं पर रहा फोकस
- देश में 11.1 लाख करोड़ रुपए के खर्च से बढ़ेगा कारोबार
- लॉजिस्टिक कॉरिडोर और रेलवे की माल ढुलाई पर फोकस
- अंतरिम बजट में एक करोड़ करदाताओं की खुली लॉटरी
- टूट गई अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों की उम्मीद
- सीएपीएफ कैंटीन को नहीं मिली 50 फीसदी जीएसटी छूट
- 40 हजार पुराने डिब्बों को वंदे भारत की तरह बदला जाएगा
- बजट भाषण में लक्षद्वीप का जिक्र, मालदीव को फिर लगेगी मिर्ची
- खेलो में हमारे युवाओं द्वारा नई ऊंचाइयों को छूने से देश गौरवान्वित
- युवाओं के लिए एक लाख करोड़ का कोष स्थापित करने का प्रस्ताव
- तकनीकी प्रेमी हमारे युवाओं के लिए यह एक स्वर्णिम काल होगा
- औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ पहुंचा
- सरकार वर्ष 2014 तक के आर्थिक हालात और मौजूदा स्थिति पर श्वेत-पत्र लाएगी
- तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनांकिकी परिवर्तन विकसित भारत के के सामने चुनौती

नई दिल्ली/भोपाल। जागत गांव हमार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के संयुक्त सदन में 57 मिनट का अंतरिम बजट भाषण दिया। इसमें मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनाईं। वित्त मंत्री ने सुबह 11: 01 बजे से बजट भाषण शुरू किया और 57 मिनट बाद 11: 58 बजे खत्म किया। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। मैं जुलाई में पूर्ण बजट पेश करूंगी। आत्मविश्वास से भरी वित्त मंत्री ने इशारा दे दिया है कि इस लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी सरकार आने वाली है। वित्त मंत्री ने यह भी बता दिया कि इस बजट में सरकार का फोकस गांवों की ओर ज्यादा है। देश की नारी शक्ति को लगातार बढ़ाने में जुटी मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में नारी शक्ति के लिए कुछ बड़ा ऐलान किया है। 'नारी शक्ति' की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कीं हैं। बजट में लखपति दीदी योजना को विस्तारित किया गया है। टारगेट दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ किया गया है। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला। एक करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं। अब तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। सरकार ने महिलाओं को 30 करोड़ कर्ज दिया। उन्होंने कहा कि नौ करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख स्वयं-सहायता समूह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनने के साथ ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिवेश में बदलाव ला रहे हैं। इनकी सफलता से पहले ही करीब एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिल चुकी है। वे दूसरों के लिए एक प्रेरणा हैं। उन्हें सम्मान देकर उनकी उपलब्धियों को मान्यता दी जाएगी। कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बढ़ाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार विकास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है जोकि सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी है। यह हर स्तर पर सभी जातियों और लोगों तक पहुंचेगा। सरकार 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें लोगों की क्षमता को बेहतर और उन्हें सशक्त बनाना होगा।

मंत्रालयों के लिए आवंटित बजट

मंत्रालय	बजट
रक्षा मंत्रालय	6.2
संचार मंत्रालय	1.37
गृह मंत्रालय	2.03
रेल मंत्रालय	2.55
ग्रामीण विकास	1.77
कृषि मंत्रालय	1.27
सड़क परिवहन	2.78
रसायन मंत्रालय	1.68
उपभोक्ता मामले	2.13

नोट-राशि लाख करोड़ में

श्वेत पत्र भी लाएगी केंद्र सरकार

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि उन वर्षों का संकट दूर कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था सर्वांगीण विकास के साथ एक उच्च सतत विकास मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार वर्ष 2014 तक हम कहां थे और अब कहां हैं विषय पर श्वेत पत्र के साथ आगे आएगी, जिसका केवल एक ही उद्देश्य है कि उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबक सीखा जा सके।

70 फीसदी महिलाओं को मकान

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70 फीसदी मकान महिलाओं को मकान दिए गए हैं। ग्रामीण इलाके में पीएम आवास योजना के तहत तैयार किए गए 70 फीसदी मकान संयुक्त मालिकाना हक वाले मामले में दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार ने 3 तलाक को गैरकानूनी करार दिया।

देश में करदाता 2.4 गुना बढ़े

प्रत्यक्ष कर संग्रह 10 साल में तीन गुना बढ़ा है। करदाता 2.4 गुना बढ़े हैं। करदाताओं का योगदान देश के विकास में काम आ रहा है। सरकार ने कर दरों को कम किया है। लागू हो चुकी नई कर योजना के तहत सात लाख रुपए तक अब कोई कर नहीं हैं। कॉर्पोरेट टैक्स भी कम हुआ है। नए फॉर्म 26 एएस से टैक्स फाइल करना आसान हुआ है। 2013-14 में 93 दिनों के बजाय अब 10 दिन में रिफंड मिल रहा है। कर दरों, आयात दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

अंतरिम बजट: टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, सैलरीड क्लास को कोई फायदा नहीं

- मध्यम वर्ग के लिए अगले पांच साल में तीन करोड़ नए घर बनाएगी सरकार
- 2014 से पहले के आर्थिक कुप्रबंधनों पर श्वेतपत्र लाएगी केंद्र सरकार
- रक्षा क्षेत्र को 6.2 लाख करोड़- पिछले साल के मुकाबले 27 हजार करोड़ का इजाफा
- टेक सेक्टर- एक लाख करोड़ का एलाव, ब्याज भी नहीं देना होगा
- वित्त वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचे के लिए परिव्यय बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ किया
- 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 फीसदी रहने का अनुमान
- छोटे पर्यटन को बढ़ावा देने लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी
- पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी
- देशभर में 09 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा
- पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए
- ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास के तहत महिलाओं को 70 फीसदी आवास मिले
- हर परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होने का अनुमान
- गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं
- भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 वर्षों में गहरा संकटात्मक परिवर्तन देखा है, भारत के लोग आज के साथ भविष्य की ओर देख रहे
- नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया
- 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए
- स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं-महिलाओं का 43 फीसदी नामांकन
- पीएम आवास के तहत 70 फीसदी घर ग्रामीण महिलाओं को दिए
- पांच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य दिया जाएगा
- छत पर सौर प्रणाली लगाना (रूफटॉप सोलराइजेशन) और फ्री बिजली
- सुविधा के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा
- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर भारत और दूसरे देशों के लिए भी एक परिवर्तनकारी कदम
- ई-बसों को प्राथमिकता देगी केंद्र सरकार
- सर्वाइकल कैंसर रोकने की कोशिश होगी
- देशभर में मिशन इंद्रधनुष में टीकाकरण बढ़ाया जाएगा
- 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे
- प्रधानमंत्री आवास का विस्तार होगा
- 5 साल में 2 करोड़ नए घर बनाए
- 12 करोड़ किसानों को कर्ज दिए
- इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर केंद्र का फोकस
- 4 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला
- 11.8 करोड़ किसान आज सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे
- 25 करोड़ लोगों को सरकार ने गरीबी से बाहर निकाला
- युवाओं को सशक्त करना सरकार की पहली प्राथमिकता
- उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28 फीसदी बढ़ा

बजट 2024-25 की मुख्य बातें

- चार प्रमुख वर्गों यानी गरीब, महिलाएं, युवा एवं अन्नदाता (किसान) को ऊपर उठाने पर प्रधानमंत्री का फोकस
- पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर आने में मदद की
- पीएम-जनधन खातों से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ का हस्तांतरण। सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत
- पीएम-स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता। 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण मिला
- पीएम-जनमन योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के विकास पर जोर
- पीएम-विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड-टू-एंड मदद

अन्नदाता का कल्याण

- पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई
- पीएम-फसल बीमा योजना के तहत चार करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई
- इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) के तहत 1,361 मंडियों को एकीकृत किया गया
- ई-नाम में तीन लाख करोड़ रुपए की खरीद-फरोख्त के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं उपलब्ध
- पीएम-आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल किया जाएगा
- छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे

चार सेक्टर पर फोकस

1. **गरीब:** सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे
2. **महिला:** करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य
3. **युवा:** स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड और 54 लाख लोगों को दोबारा से सिखाया गया
4. **किसान:** प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत देश के 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली

विकसित भारत की गारंटी

अंतरिम आम बजट समावेशी और नवोन्मेषी होने के साथ ही देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। यह विकसित भारत के चार स्तंभों युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त करेगा। यह बजट 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। बजट में निरंतरता का विश्वास है।इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। बजट में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अनुसंधान और नवाचार पर 1 लाख करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की गई है, बजट में स्टार्टअप को मिलने वाले टैक्स छूट के विस्तार का भी एलान किया गया है।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सभी वर्गों का कल्याण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट सर्वहितैषी और सर्व समावेशी है। बजट 2024-25, गरीब, महिला, युवा और किसान समेत सभी वर्गों का कल्याण करने वाला है। देश को आगे बढ़ाने का प्रयास विभिन्न विभाग कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि उनके सर्व हितैषी कामों के आधार पर सभी विभाग ध्यान देते हैं। इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो-डीएपी का उपयोग, पशुओं के लिए नई योजनाएं, पीएम मत्स्य संपदा योजना के विस्तार और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान से देश के किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा।

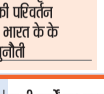

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मप्र

हर वर्ग को लाभ मिलेगा...

केंद्रीय बजट 2024 चार चीजों पर केंद्रित है। ये चार चीजें हैं- गरीब, महिलाएं, युवा और देश के किसान। प्रधानमंत्री का भी हम धन्यवाद कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में बजट बहुत ही अच्छा आया है। केंद्रीय बजट में महिलाओं की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इस बजट से हर वर्ग को लाभ मिलेगा। किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इसमें राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए पूंजीगत व्यय को 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। दो करोड़ और लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने दो करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, अब इस लक्ष्य को 3 करोड़ कर दिया गया है।

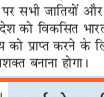

जगदीप धनड़, वित्त मंत्री, मप्र

भारत में अवसरों की कमी नहीं

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत का हर नागरिक आशा और विश्वास के साथ भविष्य की ओर देख रहा है। आज भारत में अवसरों की कमी नहीं है। सभी लोगों और सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करके विकसित संपन्न राष्ट्र की ओर भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बजट में जहां अधोसंरचनात्मक व्यय को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। वहीं गरीब, अन्नदाता, महिलाओं और युवाओं के कल्याण, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को प्राथमिकता दी गयी है।

राजेंद्र शुक्ल, डिप्टी सीएम

यह भारत को विकसित, आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनाने वाला बजट है। यह एक संदेश है कि किस तरह मोदी सरकार ने देश के विकास के लिए कार्य किया है। एशिया ही नहीं, दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा हो रही है। 10 वें स्थान से देश आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस बजट में किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ श्रमिक वर्ग का भी ख्याल रखा गया है। मनरेगा जैसी योजनाओं को दिल खोलकर बजट दिया गया है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री

मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी सरकार का यह बजट नारी शक्ति के उत्थान व विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बहनों के जीवन में बदलाव लाने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य तय किया है, वह महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, इससे हमारे देश की सुरक्षा तथा विकास को और मजबूत गति मिलेगी। हमारे किसानों की आय डबल होगी। खेती लाभ का धंधा बनेगी। सड़कों का देशभर में जाल बिछाया जाएगा।

शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम

मध्यमवर्ग को आशा थी कि सरकार इनकम टैक्स स्लैब में कोई छूट देगी, लेकिन एक बार फिर से अपना जन विरोधी चेहरा सामने लाते हुए मोदी सरकार ने आयकर में कोई छूट नहीं दी। केंद्र का यह बजट पूरी तरह से जुमलेबाजी है। चुनावी बजट है। हर वर्ग को छलने का प्रयास किया गया है। हर वर्ग को इस बजट से उम्मीद थी,लेकिन सरकार ने पानी फेर दिया। सरकार ने चुनाव को देखते हुए लुभावना बजट पेश किया है। इस बजट में न नौकरी है और न ही स्वरोजगार है।

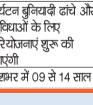

कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री

पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत से अधिक घरों की मालकिन महिलाएं हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को 30 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। केंद्र का यह बजट सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण ही देश विश्वगुरु बनने की बढ़ रहा है।

वीडी शर्मा,प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा

मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में भी पूरी ईमानदारी से चार झूठ बोले हैं। आर्थिक झूठ, सामाजिक झूठ, राजनीतिक झूठ, नैतिक झूठ। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली सरकार दावा कर रही है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। यह भाजपा का वर्ष 2024 में बोला गया सबसे बड़ा आर्थिक झूठ है। क्योंकि, मैं जिस देश में रहता और लोगों से मिलता हूं वहां गरीबों की परिभाषा अलग है। सरकारी कागजों में गरीब की उपस्थिति अलग तरह से दिखाई और दर्शायी जा रही है।

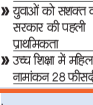

जीतू पटवारी, पीसीसी चीफ

पानी से फैलने वाली संक्रामक बीमारियां, कारण, प्रभाव और इसकी रोकथाम

» डॉ. अनीता तिवारी
» डॉ सुलोचना सेन
» डॉ सुमन संत
» डॉ अभिलाषा सिंह

पशु जन स्वास्थ्य एवं महामारी विभाग, पशु आनुवंशिकी एवम प्रजनन विभाग, पशु चिकित्सा एवम पशुपालन विस्तार शिक्षा विभाग, पशु पोषण विभाग, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा

पानी जीवन देने वाला तरल है वह एक जीवन लेने वाला घातक तरल पदार्थ भी हो सकता है। दुनिया में लगभग 3.1 प्रतिशत मौतें पानी की गन्दी और खराब गुणवत्ता के कारण होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनिया भर में 80प्रतिशत बीमारियाँ जल द्वारा उत्पन्न होती है। जलजनित रोग विश्व की जनसंख्या के लिए, विशेष रूप से विकासशील देशों में एक प्रमुख चुनौती हैं।

मानसून मौसम में खासतौर पर रुके हुए पानी की वजह से पानी से फैलने वाली संक्रामक बीमारियों की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। पानी से फैलने वाली इन बीमारियों के इलाज के लिए अक्सर लोग डॉक्टर की सलाह के बिना एंटी-बायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। जो की बहुत ही गलत आदत है और यह आदत अन्य बहुत सी गंभीर समस्याओ को बढ़ावा दे सकती है। जैसे की रोगाणुरोधी प्रतिरोध या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस।

जलजनित रोग के कारण: जल की गुणवत्ता का खराब हो जाती है जब वह औद्योगिक अपशिष्ट, मानव अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, कचरा, अनुपचारित मल, रासायनिक अपशिष्ट आदि से प्रदूषित हो जाती है। ऐसे प्रदूषित पानी को पीने या इससे खाना पकाने से जल जनित रोग और संक्रमण हो जाता है। ये बीमारियाँ नहाने, कपड़े धोने, या दूषित पानी के संपर्क में आने से भी फैल सकती हैं। इसलिए, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता में कमी किसी समुदाय में जलजनित बीमारियों के फैलने का प्रमुख कारण है।

दूषित पानी से पैदा होने वाली बीमारियाँ:
गैस्ट्रोएंट्राइटिस- इसे फूड प्वॉइजनिंग या भोजन विषाक्तता भी कहा जाता है। इस रोग में पेट और छोटी तथा बड़ी आंतों की परत में सूजन हो जाती है। हवा में नमी बढ़ने के कारण भोजन में बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। इसके लक्षण हैं पेट में मरोड़ पड़ना, उल्टी, पेचिस, अस्वस्थ या बुखार महसूस करना, सुस्ती और शरीर में दर्द, गंभीर मामलों में मल में रक्त या मवाद आदि।

टाइफॉयड बुखार: यह एक जीवाणु जनित संक्रमण है जो दूषित पानी या भोजन के कारण होता है। यह आँतों के रास्ते को प्रभावित करता है और बाद में रक्तप्रवाह में फैल जाता है। इसे आँतों का के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से हमारी आंतों को प्रभावित करता है। टाइफॉण्ड बुखार के संकेत और लक्षण इस प्रकार है- बुखार आना और ठंड लगाना, सिरदर्द , दस्त के साथ पेट दर्द, जी मिचलाना और उल्टी आना, कमज़ोरी और भूख न लगना, लिवर में सूजन, बेहोसी से अवस्था होना, नकसीर फूटना आदि। जल्दी ठीक होने में मदद करने के लिए, नियमित दवा के साथ घरेलू नुस्खे आज़माएं जैसे की ज्यादा तरल पदार्थ

पिएं, ठंडी पट्टी का इस्तेमाल करें, उबला पानी पिए, पचाने में आसान भोजन करे।

हैजा: यह एक जानलेवा बीमारी है, जो मानसून में फैलती है। यह अनहाइजीनिक/ गंदी परिस्थितियों, संदूषित भोजन और पानी के कारण होती है। यह जीवाणु आमतौर पर संक्रमण वाले व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया/ जीवाणु भोजन द्वारा शरीर में जाके आंतों में एक विष छोड़ता है जो गंभीर दस्त पैदा करता है । इसके आम लक्षण हैं- गंभीर दस्त, उल्टी, जिसकी वजह से शरीर से पानी बहुत अधिक मात्रा में निकल जाता है। मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। दस्त के कारण कुछ ही घंटों में डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो जाता है। हैजा के मामले में तुरंत इलाज की जरूरत होती है **पीलिया:** यह रोग बहुत ही सूक्ष्म विषाणु (वाइरस) से होता है। शुरू में जब रोग धीमी गति से व मामूली होता है तब इसके लक्षण दिखाई नहीं पडते हैं, परन्तु जब यह उग्र रूप धारण कर लेता है तो रोगी की आंखे व नाखून पीले दिखाई देने लगते हैं और त्वचा पीली पड़ जाती है। लोग इसे पीलिया कहते हैं। ये वायरस रोगी के मल में होतें है पीलिया रोग से पीडित व्यक्ति के मल से, दूषित जल, दूध अथवा भोजन द्वारा इसका प्रसार होता है। इसमें मुख लक्षण है - रोगी को बुखार और शरीर में दर्द रहना, भूख न लगना, चिकनाई वाले भोजन से अरूचि, जी मिचलाना और कभी कभी उल्टियाँ होना, सिर में दर्द।

हेपेटाइटिस ए: हेपेटाइटिस ए लीवर का रोग है जो वायरस हेपेटाइटिस ए के कारण होता है। जब आप दूषित पानी या भोजन के संपर्क में आते हैं। हेपेटाइटिस ए होने पर बुखार, अस्वस्थता, भूख न लगना, दस्त, मतली, पेट में दर्द, गहरे रंग का मूत्र और पीलिया जैसे लक्षण होते हैं।

अन्य मुख्य बीमारियां: इनके अलावा दूषित पानी से होने वाले रोग हैं - अमिबायसिस, जिआर्डियासिस, टोक्सोप्लास्मोसिस, शिगेलोसिस, गिनी-कृमि रोग, हेपेटाइटिस ई जैसे विषाणु, इ.कोली संक्रमण आदि।

जलजनित रोग से बचाव के लिए सावधानियां: सुनिश्चित करें कि पानी बिल्कुल साफ और रेत और मिटटी से मुक्त हो। दिखाई पड़ने वाली गंदगी को हटाने के लिए पानी को छान लें। केवल साफ और सुरक्षित पानी पिएं - पीने के लिये पानी नल, हैण्डपम्प या आदर्श कुओं को ही काम में लें। मानसून मौसम में उबला या प्यूरीफायर का पानी पीने की सलाह दी जाती है ताकि पानी के कारण होने वाली बीमारियां न फैलें। सुनिश्चित करें कि संग्रहित पानी रोगाणु रहित हो। घर के आसपास गंदगी जमा न होने दें। खुले में शौच न जाये, स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें। मल, मूत्र, कूडा करकट सही स्थान पर गड्ढा खोदकर दबाना या जला देना चाहिये।

जहां तक हो सके, बाहर का खाना न खाएं।जब भी बाहर का खाना खाएं तो डिस्पोजेबल ग्लास और प्लेट्स का इस्तेमाल करें, खासकर स्ट्रीट फूड। खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले व बाद में और शौच जाने के बाद में हाथ साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए।

विकास की भेंट चढ़ते वेटलैंड, मानव जाति के लिए संकट

मुझे याद है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शोध करते हुए अक्सर सेसाईपुरा से शिवपुरी जाना पड़ता था, क्योंकि फोन की सुविधा वही थी। रास्ते में एक सुंदर बड़ी आर्द्रभूमि होती थी, जिसे एक ओर से बांध बनाकर आसपास के खेतों से जल संग्रह के लिए बनाया गया था। किंतु प्रतिवर्ष गेहूं के फसल के समय इस आर्द्रभूमि को सूखा दिया जाता था। ऐसे उदाहरण हमने और आपने अपने आसपास देखे होंगे, जहां आर्द्रभूमि को नाना प्रकार के कार्यों के लिए सुखाकर या भरकर उपयोग में लाया जाता है। वास्तव में मानव समाज ने कभी भी आर्द्रभूमि को अहमियत नहीं दी। हमेशा इस बंजार स्थल की तरह व्यवहार किया। मैं तो कहूंगा कि हमने आर्द्रभूमि को तृषकृत किया।

आर्द्रभूमियां (वेटलैंड्स) पृथ्वी के सबसे संकटग्रस्त प्रयावासों में से एक हैं। सन 1700 में मौजूद लगभग 85 प्रतिशत आर्द्रभूमि सन 2000 तक खत्म हो गईं। कई तो विकास, खेती या अन्य उपयोगों के लिए सुखा दी गई हैं।

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सन 1900 के बाद से दुनिया की 64 प्रतिशत आर्द्रभूमियां गायब हो गई हैं। जंगलों की तुलना में तीन गुना तेजी से गायब होने से, उनका नुकसान सैकड़ों हजारों जानवरों और पौधों की प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करता है। आखिरकार समस्त मानव जाति ही संकट में नजर आ रही है। परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। एक प्रकृति संरक्षण समूह ने पाया है कि दुनिया की लगभग हर पांचवीं ड्रैगनफ्लाइज और ड्रैम्सलफ्लाई विलुप्त होने के कगार पर हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) की विलुप्तप्राय प्रजातियों की रेड डाटा सूची के अनुसार, ड्रैगन और ड्रैम्सलफ्लाई की 6,016 प्रजातियों में से लगभग 16प्रतिशत विलुप्त होने के कगार पर हैं। परिणाम स्वरूप विषाणु जनित रोगों में अप्रत्याशी वृद्धि हो रही है। मलेरिया, डेंगू आदि जैसे रोग असमय नजर आ रहे हैं। कारण ड्रैगनफ्लाइज और ड्रैम्सलफ्लाई जो कि मच्छरों के जैविक नियंत्रक हैं, उनका एवं उनके स्वस्थ आर्द्रभूमि का निरंतर विनाश होना है।

रामसर कन्वेंशन, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण वेटलैंड्स को संरक्षित करना और उनके संरक्षण और सदुपयोग को बढ़ावा देना है, के सचिवालय द्वारा जारी सन 2021 ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक के अनुसार, दुनिया भर में वेटलैंड्स क्षेत्र में उपलब्ध डाटा अनुसार 35 प्रतिशत की कमी आई है।

अकेले 1970 से प्राकृतिक आर्द्रभूमियां प्रति वर्ष 0.78प्रतिशत की दर से घट रही हैं, जो प्राकृतिक वनों की कटाई की दर से काफी अधिक है। यह आगे बताता है कि जल निकासी, प्रदूषण, आक्रामक और विदेशी प्रजातियां, अस्थिर उपयोग, बाधित प्रवाह व्यवस्था और जलवायु परिवर्तन के कारण शेष आर्द्रभूमि की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।

वास्तव में आर्द्रभूमि एक कठिन परिस्थिति से गुजर रही हैं। फिर भी, खाद्य सुरक्षा से लेकर जलवायु परिवर्तन शमन तक, आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों से कहीं अधिक भी है एवं महत्वपूर्ण भी है।

साइंस में 2022 में प्रकाशित पेपर के अनुसार, पीटलैंड्स, मैंग्रोव वन, दलदल और समुद्री घास जैसे आर्द्रभूमि धरती पर कार्बन का 20 प्रतिशत संग्रहण करते हैं, भले ही वे पृथ्वी की सतह का केवल 1 प्रतिशत कवर करते हैं।

यह उनकी उच्च कार्बन पृथक्करण दर और प्रति इकाई क्षेत्र में प्रभावी पृथक्करण दर के कारण है, जो समुद्री और वन पारिस्थितिकी प्रणालियों से कहीं अधिक है।

1971 में अपनाए जाने के बाद से, रामसर कन्वेंशन ने दुनिया भर में आर्द्रभूमि के संरक्षण और सदुपयोगिता में विभिन्न योगदान दिया है। भारतवर्ष में आज दिनांक तक 80 वेटलैंड्स रामसर साइट के रूप में घोषित किए जा चुके हैं।

दुर्भाग्य से गैर चिन्हित आर्द्रभूमियों में से अधिकतर की स्थिति क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र की नहीं है। साथ ही साथ कुछ ऐसे रामसर साइट भी नजर आते हैं, जिनको अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। घटता जलस्तर, अतिक्रमण, आक्रामक विदेशी पौधों, एवं व्यवसायिक विकास मॉडल इन आर्द्रभूमि को काल के गाल में समाहित करते जा रहे हैं।

इसके बावजूद कुछ सफल उदाहरण हैं, जो सरकार द्वारा वैज्ञानिक तरीके से पुनर्स्थापित वेटलैंड को प्रदर्शित करते हैं। इनमें एक दिल्ली विकास प्राधिकरण का दिल्ली स्थित यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क है। जहां दलदली जमीन एवं आर्द्रभूमि को स्थापित किया गया है।

भारत में किसी नदी घाटी में किए गए क्रियाशील बाढ़ क्षेत्र में आर्द्रभूमि पुनर्स्थापना का एक नायाब नमूना है। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में बाढ़ क्षेत्र विशेषता वाले आर्द्रभूमि, घास के मैदान, एवं वनों को पुनर्स्थापित किया गया है जिससे न केवल यमुना नदी को आवश्यकता के समय लाभ पहुंचता है, बल्कि इस पुनर्स्थापित पर्यावास स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों का प्राकृतिक वास बना है। साथ ही साथ नाना प्रकार के सरीसृप, घास खाने वाले वन्य जीव एवं मांसाहारी वन्य जीव वगैरह पुन: अपने ऐतिहासिक भौगोलिक वितरण सीमा क्षेत्र को प्राप्त किया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है।

महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों की रक्षा करना और आर्द्रभूमि बहाली को बढ़ावा देना न केवल जलवायु परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण शमन उपाय है, बल्कि प्राकृतिक जल अवशोषण और अवधारण क्षमता का उपयोग और विस्तार करके, बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने में भी योगदान देता है।

आवश्यकता है कि हम इन जीवनदायिनी आर्द्रभूमि को सिर्फ जल का संग्रहण समझ निरादर ना करें इसकी उपेक्षा न करें समय रहते अगर हम यह समझ पाए के पीने के पानी का प्रमुख स्रोत यह आर्द्रभूमि हमारी आवश्यकता है। आओ, मिलकर आदर सहित इन्हें संरक्षित करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अधिक आवश्यक है।

साभार

35 महीनों के निचले स्तर पर पहुंचा खाद्य मूल्य सूचकांक

वैश्विक बाजार में खाद्य कीमतों में गिरावट का जो सिलसिला पिछले साल शुरू हुआ था वो जनवरी 2024 में भी जारी रहा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के मुताबिक गेहूं-मक्के के साथ-साथ मांस की कीमतों में आई गिरावट के चलते वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक (फूड प्राइस इंडेक्स) में जनवरी 2024 के दौरान भी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि इस दौरान वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतों में उछाल जरूर देखा गया, लेकिन अनाज और मांस की कीमतों में आई गिरावट ने उसकी भरपाई कर दी है। खाद्य कीमतों में आई गिरावट का ही नतीजा है कि जनवरी 2024 में वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक करीब तीन वर्षों के अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि यह सूचकांक वैश्विक स्तर पर जिन खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है उनकों ट्रैक करता है। आंकड़ों की मानें तो जनवरी 2024 में खाद्य मूल्य सूचकांक 118 अंक रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले महीने दिसंबर 2023 में 119.1 अंक दर्ज किया गया था। मतलब की यह पिछले महीने के मुकाबले जनवरी में करीब एक फीसदी कम रहा। वहीं यदि पिछले साल जनवरी 2023 से इसकी तुलना करें तो इस साल जनवरी में सूचकांक 10.4 फीसदी कम रहा। बता दें कि पिछले 35 महीनों में यह सूचकांक कभी भी इतना नीचे नहीं गया। इससे पहले फरवरी 2021 में सूचकांक 116.5 अंक दर्ज किया गया।

एफएओ ने जो अपडेट जारी किए हैं उनके मुताबिक अनाज मूल्य सूचकांक पिछले महीने की तुलना में 2.2 फीसदी नीचे चला गया है। गौरतलब है कि जहां दिसंबर 2023 में यह इंडेक्स 122.8 अंक दर्ज किया गया था वो जनवरी 2024 में घटकर 120.1 अंक पर पहुंच गया है। सरल शब्दों में कहें तो जनवरी में गेहूं की कीमतों में गिरावट देखी गई है, क्योंकि दक्षिण के देशों से आपूर्ति बढ़ी है, जिसकी वजह से अंतराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। अच्छी पैदावार से मक्के की कीमतों में गिरावट आई है, खासकर अर्जेंटीना और अमेरिका में इसकी अच्छी पैदावार हुई है, जिससे आपूर्ति बढ़ी है। वहीं यदि वनस्पति तेल के लिए जारी सूचकांक की बात करें तो दिसंबर की तुलना में इसमें 0.1 फीसदी की मामूली वृद्धि हुई है। हालांकि यह अभी भी पिछले साल की तुलना में 12.8 फीसदी कम है। यह बदलाव वैश्विक स्तर पर पाम और सूरजमुखी के तेल की कीमतों में आई मामूली बढ़ोतरी के कारण है। वहीं डेयरी मूल्य सूचकांक को देखें तो वो करीब-करीब दिसंबर जितना ही रहा, हालांकि वो एक साल पहले की तुलना में 17.8 फीसदी कम था। जनवरी में, एशिया से अधिक मांग के चलते मखान और दूध की कीमतों में वृद्धि हुई है।

काली हल्दी से एक एकड़ में 10 लाख की कमाई

पीली हल्दी से भी महंगी बिकती है कैंसर की दवा के रूप में कारगर

आइए जानते हैं काली हल्दी की खेती करने वाले आकाश चौरसिया की ज़ुबानी में पूरी कहानी

सागर जिले के कपूरिया गांव के रहने वाले आकाश चौरसिया ने ढाई एकड़ में काली हल्दी की खेती की है। इसमें उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। काली हल्दी औषधीय फसल है। कैंसर की दवा बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कीमत पीली हल्दी के मुकाबले ज्यादा मिलती है। जागत गांव हमार अपने इस अंक में किसानों को मिलवा रहा है सागर के ग्राम कपूरिया के किसान आकाश चौरसिया से। आकाश ने करीब 15 साल पहले किराए की 10 डिसमिल जमीन लेकर मल्टीलेयर प्राकृतिक जैविक खेती शुरू की थी। आज कपूरिया में आकाश का 16 एकड़ का फार्म है। यहां वे कई प्रकार की अन्य फसलें भी लगा रहे हैं।

सागर। जागत गांव हमार

मैंने पहली बार 2023 में मल्टीलेयर प्रणाली से काली हल्दी की खेती शुरू की। ढाई एकड़ खेत में काली हल्दी लगाई थी, जिसमें प्रति एकड़ 22 से 25 क्विंटल पैदावार हुई। इस बार भी फसल तैयार हो गई है और खुदाई शुरू कर दी है। यदि फसल लगाने की प्रक्रिया को ठीक तरह से किया जाए तो मल्टीलेयर पद्धति से खुले खेत में भी काली हल्दी का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। इसकी खेती में प्रति एकड़ ढाई लाख रुपए तक की लागत आती है। काली हल्दी की खेती में सबसे महंगा इसका बीज होता है। इसके अलावा निदाई-गुड़ाई, कीटनाशक, सिंचाई समेत अन्य मजदूरी लगती है। मल्टीलेयर पद्धति से काली हल्दी की खेती करने पर 22 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन लिया जा सकता है। वहीं खुले खेत में खेती करने पर 10 से 15 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है।

प्रति एकड़ ढाई लाख की लागत से 10 लाख रुपए तक मुनाफा कमाया जा सकता है। बेहतर तरीके से खेती की जाए तो यह मुनाफा 15 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। क्योंकि बाजार में गीली काली हल्दी 500-900 रुपए प्रति किलो तक बिकती है। वहीं काली हल्दी का पाउडर 2500-3500 रुपए किलो बिकता है। मध्यप्रदेश समेत अन्य प्रदेश और देशों में काली हल्दी और उसके पाउडर की डिमांड रहती है। यदि किसानों को उपज बेचने में परेशानी आती है तो हम ही उनकी फसल खरीद लेते हैं। मल्टीलेयर खेती की वजह से मैं एक साथ चार फसलों का उत्पादन लेता हूं। खेत में बांस की मदद से अस्थाई देशी ग्रीन हाउस तैयार किया है। काली हल्दी के साथ उसी खेत में पपीता, कुंदरू, ककड़ी, सहजन जैसी फसलें भी लगाता हूं। जमीन में हल्दी के ऊपर पालक, धनिया व अन्य भाजी लगाता हूं। हल्दी को जमीन के ऊपर आने में करीब एक माह का समय लग जाता है। तब तक मैं मिट्टी की ऊपरी सतह पर अन्य सब्जियों की पैदावार ले लेता हूं। काली हल्दी की बुवाई का उचित समय बारिश का मौसम माना जाता है। इसकी बुवाई का उचित समय जून-जुलाई होती है। हालांकि, सिंचाई का साधन होने पर इसे मई माह में भी बोया जा सकता है।

पत्तों में रुई मिलाकर तकिया बनाते हैं

फसल का उत्पादन लेने के बाद पते का भी उपयोग कर रहे हैं। सूखे पत्तों को इई कर तेल निकालते हैं और पूरी तरह सूखने पर उनका उपयोग तकिया बनाने में करते हैं। हल्दी के पत्तों के साथ रुई मिलाकर तकिया बनाया जाता है जो 500 रुपए तक में बिक जाता है। यह तकिया काफी आरामदायक होता है।

क्या है मल्टीलेयर फार्मिंग

मल्टीलेयर फार्मिंग जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें एक ही स्थान पर एक साथ कई प्रकार की फसलों की खेती की जा सकती है। इस विधि में उन फसलों का चयन किया जाता है जिन्हें जमीन के अंदर आसानी से उगाया जा सकता है। इस तरह की खेती में कुछ फसल बेलों पर उगाई जाती हैं। वहीं, कुछ फसलें जमीन पर एक निश्चित दूरी पर उगाते हैं। इस विधि का उपयोग करके किसान एक ही भूमि में एक साथ कई फसलें उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।

खेती के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए

काली हल्दी की खेती के लिए उष्ण जलवायु अच्छी रहती है। इसके लिए 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेट का तापमान सही होता है। इसके पौधे पाले को भी सहन कर लेते हैं। साथ ही विपरीत मौसम में भी अपना अनुकूलन बनाए रखते हैं। इसकी खेती के लिए बलुई, दोमट, मटियार या ऐसे भूमि जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो, बेहतर होती है। इसके विपरीत चिकनी काली, मिश्रित मिट्टी में कंद बढ़ते नहीं हैं। इसकी खेती के लिए मिट्टी में भरपूर जीवाश्म होना चाहिए। जलभराव या कम उपजाऊ भूमि में इसकी खेती नहीं रहती है। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच 5 से 7 के बीच होना चाहिए।

ऐसे तैयार करते हैं पौधा

काली हल्दी की रोपाई इसकी पौध तैयार करके भी की जा सकती है। इसके पौध तैयार करने के लिए इसके कंदों की रोपाई ट्रे या पॉलीथिन में मिट्टी भरकर की जाती है। इसके कंदों की रोपाई से पहले बाविस्टिन की उचित मात्रा से उपचारित कर लेना चाहिए।

काली हल्दी में होते हैं औषधीय गुण

काली हल्दी का उपयोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी समेत अन्य बीमारियों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग दवा बनाने में भी होता है। काली हल्दी मजबूत एंटीबायोटिक गुणों के साथ चिकित्सा में जड़ी-बूटी के रूप में प्रयोग की जाती है। कोलेस्ट्रॉल के लिए कारगर साबित होती है, इसलिए इस हल्दी की कीमत ज्यादा होती है। इसमें एंटीफंगल, एंटी अस्थमा, एंटीऑक्सिडेंट, एनाल्जेसिक, लोकोमोटर डिप्रेसेंट, एंटीकॉन्वेलसेंट, एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-अल्सर और मांसपेशियों को आराम देने वाले तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। किसान आकाश कहते हैं कि चमत्कारिक गुणों की वजह से काली हल्दी जानी जाती है। इसका उपयोग मुख्यतः सौंदर्य प्रसाधन व रोग नाशक दोनों तरह से किया जाता है। यह मजबूत एंटीबायोटिक गुणों के साथ चिकित्सा में जड़ी-बूटी के रूप में प्रयोग की जाती है। काली हल्दी का प्रयोग घाव, त्वचा रोग, पाचन और लिवर की समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है।

कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशन कन्वेंशन सेंटर में हुआ मंथन

खरीफ फसलों की एमएसपी निर्धारण के लिए पश्चिमी राज्यों की बैठक

भोपाल। जागत गांव हमार

भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पश्चिमी राज्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण पर मंथन किया गया। बैठक में मध्यप्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केन्द्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव के सदस्य शामिल हुए।

बैठक में अध्यक्ष, कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार विजयपाल शर्मा ने आयोग के सभी स्टेक होल्डर, किसान, सरकार, व्यापारी और अन्य प्रतिभागियों से आपसी व्यापक चर्चा कर आयोग को अनुशंसाएं देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर की चर्चाओं में खरीफ फसलों, दलहन-तिलहन के आयात-निर्यात, उपभोक्ताओं की मांग, उपार्जन, उत्पादन की लागत, अनुसंधान एवं समर्थन मूल्य के आंकलन के आधार पर अनुशंसाएं की जाएं। सदस्य सचिव कृषि लागत एवं मूल्य आयोग श्री अनुपम मित्रा ने समर्थन मूल्य के लिए राज्यों से धान, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार, दलहन-

तिलहन फसलों, मसाला फसलों के लिए आयोग से अनुशंसाएं लेने का अनुरोध किया। आयोग के सदस्य रतनलाल डागा ने लागत मूल्यों को कम करने के लिये उपार्जन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, सिंचाई की उचित व्यवस्था के साथ ही विपणन के समुचित प्रबंधों की आवश्यकता जताई। अध्यक्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग महाराष्ट्र पाशा पटेल ने विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न खरीफ फसलें मुख्यत: सोयाबीन, कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रस्तावित दरों की अनुशंसाएं आयोग से की। उन्होंने विभिन्न राज्यों की दरों का तुलनात्मक एवं तथ्यात्मक विश्लेषण कर अंतर की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग, वर्षा की स्थिति अनुसार फसलों का निर्धारण किया जाना चाहिए।

आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया

बैठक के तकनीकी सत्र का शुभारंभ अपर मुख्य सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश अशोक बर्णवाल ने किया। उन्होंने आयोग के समक्ष मध्यप्रदेश की सिंचाई, सिंचाई पम्प, कृषि यंत्रीकरण, ट्रेक्टर, विभिन्न फसलों के उत्पादन में देश में विशिष्ट स्थान संबंधी वस्तु-स्थिति आयोग के समक्ष रखी। उन्होंने उपार्जन में कृषि उपजों पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित लिमिट को बढ़ाने का अनुरोध किया। बैठक में अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार रखे। बैठक में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रूपरेखा, गतिविधियों, कार्य-प्रणाली और उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। बैठक में कृषक समितियों को सुदृढ़ बनाने, कस्टम हायरिंग सेंटर को लोकप्रिय बनाने, राजस्थान-महाराष्ट्र में मिलेट्स के क्षेत्र को विस्तृत करने पर जोर दिया गया। बैठक में दाल उत्पादन के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

मध्यप्रदेश को कृषि उत्पादों के निर्यात में मिली बड़ी सफलता

ओमान के लिए शुष्क सोयाबीन दूध पावडर की पहली खेप रवाना

भोपाल। जागत गांव हमार

कृषि प्र-संस्कृत खाद्य निर्यात प्राधिकरण (एपीडा) ने प्रदेश के कृषि निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। एपीडा के सहयोग से मध्यप्रदेश के एक्सपोर्टर द्वारा ओमान के लिये शुष्क सोयाबीन दूध पावडर की पहली खेप की गाड़ी को हरी-झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर एपीडा के जनरल मैनेजर डॉ. वीके विद्यार्थी, एपीडा के बोर्ड मेम्बर संतोष गोयल, एक्सपोर्टर मैसर्स बॉयोनाइट्रेंट्स प्रायवेट लिमिटेड भोपाल के प्रतिनिधि और इम्पोर्टर मैसर्स इंटरनेशनल टूरिज्म रेस्टॉरेंट कम्पनी ओमान के प्रतिनिधि मौजूद रहे। भारत सरकार द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एपीडा निर्यातकों को अपने उत्पाद विदेशों में निर्यात करने में आवश्यक सहयोग मुहैया कराता है। एपीडा की मध्यस्थता से ओमान के साथ बॉयोन्यूट्रेंट (इंडिया) प्रायवेट लिमिटेड के मध्य दीर्घकालिक अनुबंध हुआ है, जिसमें एक निश्चित मात्रा में शुष्क सोयाबीन मिल्क पावडर नियमित रूप से ओमान भेजा जाएगा। इसका प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों को मिलेगा तथा कृषि उत्पादों के निर्यात की नई संभावनाओं का उदय होगा। एपीडा का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुसूचित उत्पादों को बढ़ावा देना है। एपीडा के प्रयासों से देश के विभिन्न राज्यों से कई नए उत्पाद विदेशों में सफलतापूर्वक निर्यात किए जा रहे हैं।

सोया मिल्क पावडर सभी परीक्षण मानकों पर खरा उतरा

ओमान को शुष्क दूध पावडर भेजने वाले निर्यातक ने बताया कि देश में उच्च प्र-संस्करण लागत के कारण सीमित मात्रा में विनिर्माण कम्पनियां सोया मिल्क पावडर का उत्पादन कर रही है। उन्होंने बताया कि उनकी कम्पनी देश में रियल, हल्दीराम और अन्य कम्पनियों को सोया मिल्क पावडर की आपूर्ति कर रहे हैं। ओमान के इम्पोर्टर ने बताया कि मध्य पूर्व के देशों में भारतीय उत्पादों की बहुत माँग है। उन्होंने बताया कि गुणवत्ता मानकों और खाद्य सुरक्षा मानदंडों के पालन में कड़ाई होने से बाजार में स्थापित होने में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि भारत के एक्सपोर्टर द्वारा सप्लाई किया जा रहा सोया मिल्क पावडर सभी परीक्षण मानकों पर खरा उतरा है। इसीलिये कम्पनी से दीर्घकालिक अनुबंध किया है और आशा है कि भविष्य में और भी इम्पोर्टर भारतीय उत्पादों का आयात करेंगे।

दुग्ध उत्पादों की शुद्धता और गुणवत्ता का रखा जाए ध्यान

पशुपालन मंत्री ने सहकारी दुग्ध संघ का किया निरीक्षण

भोपाल। जागत गांव हमार

पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा है कि दुग्ध संयंत्रों में दुग्ध उत्पादों की शुद्धता और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड भोपाल से संबद्ध भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा सांची ब्रांड के उत्पाद शुद्धता के साथ जांच परखकर पूरी गुणवत्ता के साथ बनाए जा रहे। इसके लिए सभी संबंधित बधाई के पात्र हैं। राज्य मंत्री लखन पटेल ने भोपाल सहकारी दुग्ध संघ पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने दुग्ध संयंत्रों में दूध प्रोसेसिंग, दुग्ध उत्पादों की निर्माण विधि, उनकी पैकिंग, लैब टेस्टिंग की प्रक्रिया को देखा और दूध संग्रहण से लेकर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के विपणन की जानकारी प्राप्त की। दूध और दुग्ध उत्पादों की विधि के संबंध में प्रबंधक, संयंत्र संचालन अजय सिरोही और लैब टेस्टिंग की विधि के बारे में प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रण प्रज्ञा झा ने विस्तार से बताया।

टेस्टिंग प्रक्रिया को सराहा

मंत्री पटेल ने संयंत्रों में बनने वाले दुग्ध उत्पादों और दूध लैब टेस्टिंग प्रक्रिया की सराहना की। इस अवसर पर एमपीसीडीएफ भोपाल के प्रबंध संचालक डॉ. सतीश कुमार एस, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरपीएस तिवारी, प्रीतम सिंह लोधी, गोविंद सिंह आदि उपस्थित थे।

कृषि मंत्री से महाराष्ट्र के पाशा पटेल ने की सौजन्य भेंट

भोपाल। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना से श्यामला हिल्स स्थित निवास पर पाशा पटेल ने सौजन्य भेंट की। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग महाराष्ट्र के अध्यक्ष पटेल कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में खरीफ फसल एमएसपी निर्धारण के लिए आयोजित पश्चिमी राज्यों की बैठक में सम्मिलित होने के लिए भोपाल आये हैं। कृषि मंत्री कंषाना और महाराष्ट्र के पटेल ने किसानों के हित में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने परस्पर विश्वास व्यक्त किया कि किसानों के हित में सदैव साथ रहेंगे।

देश का अग्रणी राज्य एमपी! उद्यानिकी फसलों का उत्पादन 390 लाख मीट्रिक टन

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत संरक्षित खेती की तकनीकी और फसल प्रबंधन विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का शुभारंभ उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने किया। इस अवसर मंत्री ने कहा कि किसान संरक्षित खेती की नवीन तकनीक के इस्तेमाल से फसल उत्पादन को दुगना कर सकते हैं। किसान समृद्ध होगा, तभी देश और प्रदेश समृद्ध बनेगा। मध्यप्रदेश में गत वर्षों में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश में इनका उत्पादन साढ़े चार लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 390 लाख मीट्रिक टन हो गया है। वर्तमान में मध्यप्रदेश उद्यानिकी फसल उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है।

किसान शासन की योजनाओं का उठाएं लाभ

मंत्री कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएं और मार्गदर्शी कार्यक्रमों का संचालन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब शिक्षित युवाओं द्वारा भी रोजगार के रूप में अपनाना प्रारंभ किया गया है। युवा किसान फसल की बोनी से पूर्व मिट्टी के परीक्षण, मिट्टी की माँग के अनुसार उर्वरकों का उपयोग और पॉली हाउस जैसे संरक्षित फसल तकनीक से अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि संरक्षित खेती की नवीन तकनीक को और लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है किसान शासन की अनुदान व प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने हॉर्टिकल्चर के साथ-साथ फ्लोरीकल्चर को भी अपनाने की सलाह किसानों को दी। संगोष्ठी में प्रदेश और प्रदेश के बाहर से आए वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को नवीन तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की जा रही है। संगोष्ठी में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री मोहन जाट, स्थाई समिति के सभापति अशोक मीणा सहित उद्यानिकी विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक और बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसान उपस्थित थे।

सरकार ने पशुपालन अवसंरचना कोष को दी मंजूरी

अब आसानी से शुरू कर सकेंगे पशु पालन क्षेत्र में किसान अपना बिजनेस

भोपाल। जागत गांव हमार

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। इस कड़ी में सरकार ने पशुपालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पशु पालन अवसंरचना विकास कोष (आईडीएफ) को मंजूरी दे दी है। गत दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) को 29,610.25 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2025-26 तक अगले तीन वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। सरकार के मुताबिक यह योजना डेयरी प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण, मांस प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण, पशु चारा संयंत्र, नस्ल गुणन फार्म, पशु अपशिष्ट से धन प्रबंधन (कृषि-अपशिष्ट प्रबंधन) और पशु चिकित्सा वैक्सीन और दवा उत्पादन सुविधाओं के लिए निवेश को प्रोत्साहित करेगी।

बैंक ऋण पर मिलेगी ब्याज में छूट: पशुपालन अवसंरचना कोष के तहत इच्छुक व्यक्ति पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने के लिए आसानी से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। भारत सरकार अनुसूचित बैंक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), नाबार्ड और एनडीडीबी से 90 प्रतिशत तक ऋण के लिए दो साल की मोहलत सहित 8 वर्षों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ निजी कंपनियाँ, एफपीओ, एमएसएमई, धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनियां ले सकेंगी। जिससे अब डेयरी सहकारी समितियां डेयरी संयंत्रों के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण का भी लाभ मिलेगा। योजना के तहत भारत सरकार एमएसएमई और डेयरी सहकारी समितियों को 750 करोड़ रुपए के ऋण गारंटी कोष से उधार लिए गए ऋण की 25 प्रतिशत तक ऋण गारंटी भी प्रदान करेगी।

इन क्षेत्रों में कर सकेंगे बिजनेस

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष पशुपालन क्षेत्र में निवेश करने का अवसर देता है। योजना के तहत मूल्यवर्धन, कोल्ड चेन और डेयरी, मांस, पशु चारा इकाई, पोल्ट्री फार्म, पशु चिकित्सा औषधि/वैक्सीन, पशुओं के अपशिष्ट से धन प्रबंधन, नस्ल गुणन फार्म आदि के लिए नई इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। सरकार के मुताबिक इस योजना के शुरू होने से अब तक देश में 141.04 लाख लीटर प्रति दिन दूध प्रसंस्करण क्षमता, 79.24 लाख मीट्रिक टन फीड प्रसंस्करण क्षमता और 9.06 लाख मीट्रिक टन मांस प्रसंस्करण क्षमता को आपूर्ति श्रृंखला में जोड़कर गहरा असर डाला है। यह योजना डेयरी, मांस और पशु चारा क्षेत्र में प्रसंस्करण क्षमता को 2-4 प्रतिशत तक बढ़ाने में सक्षम है।

35 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

सरकार के अनुसार यह योजना उद्यमिता विकास के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 35 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन का एक माध्यम होगी। इस योजना का उद्देश्य पशुपालन क्षेत्र से धन सृजन करना है। पशुपालन अवसंरचना कोष से अब तक लगभग 15 लाख किसानों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है। यह योजना किसानों की आय को दोगुना करने, निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से पशुधन क्षेत्र का दोहन करने, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए नवीनतम तकनीकों को लाने और पशुधन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में कारगर साबित होगी।

जिपं सीईओ बैतूल अक्षत जैन ने कॉफी का पौधा रोपकर किया परियोजना का श्रीगणेश

बैतूल। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल अक्षत जैन द्वारा केन्द्र का भ्रमण किया एवं जिले मे काफी उत्पादन की संभवनाओं पर केन्द्र के वैज्ञानिकों से विचार विमर्ष किया भ्रमण के दौरान जैन ने फसल संग्रहालय, प्राकृतिक खेती इकाई, प्रदर्शनी कक्ष, बकरी पालन, बटेर पालन, मातृवृक्ष उद्यान, आदि विभिन्न इकाइयों का अवलोकन किया।

केंन्द्र प्रमुख डॉ. व्हीके वर्मा द्वारा केन्द्र की विभिन्न परियोजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। डॉ. संजीव वर्मा द्वारा बकरी की नस्ल सिरोही की जिलें मे संभवनाये एवं खेतों मे फसल अवशेषों को जलाने से बचाने के लिए हैप्पी सीडर मशीन की विषेषताएं और केन्द्र द्वारा निर्मित डाक्युमेंट्री फिल्म के माध्यम से केन्द्र की उपलब्धियों के बारे मे विस्तार से बताया। वैज्ञानिक डॉ. संजय जैन के द्वारा जिले मे कॉफी उत्पादन की संभावनाओं के संबंध मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा चाही गयी जानकारी प्रदान की। डॉ. इंगले ने कॉफी प्रसंस्करण के बारे में और डॉ. मेघा दुबे ने प्राकृतिक खेती एवं उसके घटकों की जानकारी दी। भ्रमण के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल अक्षत जैन द्वारा केन्द्र पर कॉफी के पौध रोपण किया।

सर्वप्रथम मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उपसंचालक उद्यानिकी, बैतूल आरके कोरी एवं केन्द्र वैज्ञानिकों के साथ उद्यानिकी विभाग की पौधशाला, बैतूल बाजार में बैठक का आयोजन किया जिसमे जिले मे कॉफी उत्पादन एवं प्रसंस्करण की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की एवं आगामी कार्य योजना बनाने के लिए निर्देशित किया। कार्यक्रम का समापन डॉ. व्हीके वर्मा द्वारा जैन को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह की भेंट द्वारा किया गया।

प्रदेश में तुअर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में सौजन्य भेंट की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में तुअर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत सरकार का प्रोत्साहन मिलने से प्रदेश में दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी। प्रतिनिधि मंडल में भारत सरकार और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) के अध्यक्ष प्रो. विजय पॉल शर्मा तथा आयोग के सदस्य डॉ. नवीन पी सिंह, अनुपम मित्रा और रतन लाल डागा शामिल थे। इस अवसर पर किसान कल्याण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उगाई गईं फसलें, पहले प्रयोग में मिली सफलता

नई दिल्ली/भोपाल। जागत गांव हमार

आज के वक्त में हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा है। हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई को लेकर तरह-तरह के प्रयोग हो रहे हैं। इसी कड़ी में खेती-किसानी के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। किसान तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के बारामती जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकी से फसलें उगाई गई हैं। बारामती में पहली बार कृषि में किया गया यह प्रयोग सफल भी रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बारामती जिले में गन्ने के साथ-साथ भिंडी, टमाटर, मिर्च, तरबूज, कद्दू, फूल, पत्तागोभी जैसी फसलें उगाई गई हैं। इसमें हर फसल की योजना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है। फसल प्रबंधन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही किया जा रहा है।

कैसे एआई ने किसानी में निभाया रोल- इस संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ तुषार जाधव ने बताया कि विभिन्न फसलों में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के सेंसर हैं, जिनसे फसलों के बारे में जानने में मदद मिलती है। इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पलाश, हवा का तापमान और हवा की गति और हवा की नमी को मापने की प्रणाली के साथ-साथ वायु रोगों की सूक्ष्म निगरानी के लिए भी सेंसर हैं।

कैसे काम करती है तकनीक

इसके साथ ही इसमें एक सेंसर प्रणाली है जो पानी को मापती है, मिट्टी की लवणता की जांच करती है और मिट्टी में फसलों को प्रभावित करने वाली विद्युत चालकता की भी जांच करती है। यह सिस्टम हर आधे घंटे में जमीन और जमीन के बाहर और हवा में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी सेंसर के जरिए सैटेलाइट को और सैटेलाइट के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर को भेजता है। उससे, एआई प्रणाली संबंधित किसान को पर्याप्त जानकारी प्रदान करती है। इस सूचना की मदद से किसान मिट्टी में कितना पानी देना है, कितना उर्वरक देना है, किस प्रकार का उर्वरक देना है और कितना देना है जानकारी पाता है। बता दें, कृषि के क्षेत्र में एआई का प्रयोग पहली बार किया गया। इस प्रयोग से सफलता भी मिली है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी खेती में एआई के इस्तेमाल की पहल की है और बारामती में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बीच इस संबंध में प्रयोग चल रहे हैं।

मंत्री बोले-एक लाख का लोन के साथ 15 हजार की किट भी देगी राज्य सरकार

गांव में विलुप्त हुनर को फिर से युवाओं को सिखाएंगे

भोपाल। जागत गांव हमार

गांव में विलुप्त हुए हुनर को फिर से बच्चों को सिखाएंगे। साथ ही स्व-रोजगार शुरू करने के लिए एक लाख का लोन और 15 हजार की किट भी देंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में 18 विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल ने यह बात पीएसएस केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में परिप्रेक्ष्य और प्रथाएं पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी समापन पर कही। उन्होंने संस्थान में स्थापित कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित सेल्फी प्वाइंट और आईओटी बेस्ड इरिगेशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम का उद्घाटन किया। संगोष्ठी में देशभर से आए शोधार्थियों ने व्यावसायिक शिक्षा को लेकर अपने शोध प्रस्तुत किए। राज्य मंत्री ने कहा कि हमने मध्यप्रदेश को कौशल युक्त-बेरोजगार मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए प्रशासन के साथ-साथ देश व प्रदेशों में काम कर रहे व्यावसायिक संस्थान व शिक्षक मिलकर कार्य करेंगे तो हम निश्चित ही युवाओं को कौशलयुक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को जल्द पूरा कर लेंगे।

पूरे मनोयोग से काम करेंगे

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुसार देश को स्किल केपिटल ऑफ यूनिवर्स बनाने के लिए पूरे मनोयोग से काम करेंगे। राज्य मंत्री टेटवाल ने हाल ही में जारी आम बजट में कौशल, व्यावसायिक शिक्षा के लिए किए गए प्रावधानों के बारे में बताया तथा कहा कि मप्र में भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में 22 नए आईटीआई बनाने की मंजूरी दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

ड्रोन दीदी योजना से मिलेगी उड़ान | मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 8 से 10 हजार रुपए तक का स्टायपेंड दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 को लागू करने में मध्यप्रदेश अग्रणी है। स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से एक करोड़ 40 लाख लोगों स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। ग्लोबल स्किल्स पार्क में बेहतरीन तकनीकी शिक्षा दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना में इस वर्ष पूरे देश में 15 हजार महिला स्व-सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑटोमोटिव सेक्टर स्किल काउंसिल और मानव संसाधन प्रमुख गरिमा झांब ने ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल की भूमिका एवं जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला।

छात्रों ने ड्रोन बनाकर किया प्रदर्शन

स्कोप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अजय कुमार भूषण ने कहा कि इण्डस्ट्री और एकेडमिया के बीच समन्वय होना चाहिए। इण्डस्ट्री की जरूरत के अनुसार ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएं। कार्यक्रम में पीएसएससीआईवीई के संयुक्त निदेशक डॉ. दीपक पालीवाल ने संगोष्ठी के उद्देश्यों के बारे में बताया। कार्यक्रम समन्वयक प्रो. सौरभ प्रकाश द्वारा संगोष्ठी के सत्रों के मुख्य अंशों की रिपोर्टिंग प्रस्तुत की। संस्थान चल रहे बूटकैंप के दूसरे दिन राजधानी के चार स्कूलों के 47 छात्र-छात्राओं ने स्वयं ड्रोन बनाकर विशेषज्ञों के समक्ष प्रदर्शन किया। राज्य मंत्री ने विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया।

-सरकार ग्रामीण क्षेत्र पर 2.65 लाख करोड़ खर्च करेगी

कृषि क्षेत्र के लिए बजट बढ़कर 1.45 लाख करोड़ केंद्र ने किया

भोपाल। जागत गांव हमार

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश कर दिया है। अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने अनुमानित खर्च के लिए कुल 47.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें से सर्वाधिक अनुमानित बजट 5.44 लाख करोड़ रुपए परिवहन सेक्टर के लिए तय किए गए हैं। दूसरे नंबर पर रक्षा क्षेत्र को सर्वाधिक 4.54 लाख करोड़ का अनुमानित बजट मिला है। जबकि, कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने 1.46 लाख करोड़ का अनुमानित खर्च बजट पेश किया है, जो बीते वित्त वर्ष में पेश किए गए बजट से 20 हजार करोड़ अधिक है। विभिन्न विभागों की स्कीम्स पर दी जाने वाली सब्सिडी योजनाओं के लिए 3.81 लाख करोड़ का बजट रखा है।

वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यह रकम बीते वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को दी गई 1.25 लाख करोड़ रुपए से 20 हजार करोड़ अधिक है। इस रकम को सरकार पीएम किसान निधि, फसल बीमा योजना समेत कृषि क्षेत्र की अन्य योजनाओं पर खर्च किया जाएगा।

ग्रामीण विकास पर होंगे 2.65 लाख करोड़ खर्च - केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास को भी प्राथमिकता में रखा है। इस सेक्टर की योजनाओं पर खर्च के लिए 2.65 लाख करोड़ का बजट दिया है। यह रकम आगामी एक साल में विभिन्य योजनाओं पर खर्च की जानी है। इसके तहत सरकार ने मनरेगा योजना का बजट भी 26 हजार करोड़ बढ़ा दिया है, क्योंकि, बीते वित्त वर्ष में मनरेगा पर 60 हजार करोड़ रुपए का बजट दिया गया था पर 2024-25 के लिए 86 हजार करोड़ का अनुमानित बजट रखा गया है।

मनरेगा का बजट बढ़ाया

बजट 2024 में ग्रामीण सेक्टर के लिए कुछ बड़े ऐलान किए हैं, जिनमें मनरेगा का बजट बढ़ाना प्रमुख है। केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का बजट 26 हजार करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। पिछली बार यानी 1 फरवरी को सरकार ने कुल 60 हजार करोड़ जारी किया था। बजट बढ़ने से 14 करोड़ से अधिक मनरेगा मजदूरों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मिलते रहने को भी सरकार ने पुख्ता कर दिया है।

मनरेगा का बजट 86 हजार करोड़

वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश करते हुए मनरेगा के तहत खर्च की जाने वाली रकम को 60 हजार करोड़ से बढ़ाकर 86 हजार करोड़ करने की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने पिछली बार बजट में मनरेगा योजना के लिए 60 हजार करोड़ का बजट घोषित किया था, जो उससे पहले 2022 के लिए जारी किए गए 73 हजार करोड़ के बजट से 18 फीसदी कम था।

इसलिए बढ़ा मनरेगा का बजट

मनरेगा मजदूरों को आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के तहत जोड़ा गया है। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों से कहा था कि इससे मनरेगा मजदूरी का भुगतान सीधे खाते में पहुंच जाएगा, लेकिन, जनवरी 2024 के पहले सप्ताह तक करीब 5 करोड़ मजदूरों को एबीपीएस से नहीं जोड़ा जा सका।

14.35 करोड़ सक्रिय मनरेगा श्रमिक

मनरेगा योजना के तहत कुल 25.94 करोड़ मजदूर रजिस्टर हैं। इनमें से 14.35 करोड़ को सक्रिय मजदूर के रूप में दर्शाया गया है। इन मजदूरों ने बीते 3 साल में कम से कम एक दिन काम किया है। एबीपीएस के लिए अयोग्य 5 करोड़ ज्यादा मनरेगा मजदूरों का सिस्टम से बाहर होना आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार के लिए यह बड़ी परेशानी का कारण बन सकता था। इसके लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों से एबीपीएस मामले में उदार रुख अपनाने को कहा था। अब सरकार ने बजट बढ़ाकर मजदूरों को साधने की कोशिश कर ली है।

ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद कार्यों मिलेगी मंजूरी

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में होंगे 20 लाख तक के काम

उमरिया। जागत गांव हमार

केंद्र शासन व्दारा संचालित प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत शासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों मे प्राथमिकता के अनुसार अधोसंरचनात्मक कार्य किए जा सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक ग्राम में 20 लाख रुपए तक के कार्य ग्राम सभा के अनुमोदन के आधार पर किए जा सकते हैं। जिला स्तरीय आदि आदर्श ग्राम समिति ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में प्रथम चरण मे चयनित ग्रामों से प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित करते हुए आनलाइन फीडिंग कराने का निर्णय लिया गया। जिन 10 सेक्टेर को चिन्हित किया गया है, उनमे आंगनबाड़ी भवन पहुंच मार्ग, बाउंड्रीवाल निर्माण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, शौचालय की व्यवस्था, पेयजल, किचनशेड, पुस्तकालय का संचालन, उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, आजीविका भवन, लघु वनोपज, संग्रहण केंद्र, उचित मूल्य दुकान का निर्माण, नल जल योजना के तहत पाइप लाइन विस्तार, जल संरक्षण की गतिविधियां, सांस्कृतिक भवन का निर्माण, खेल से संबंधित गतिविधियां, बिजली के विस्तार आदि की गतिविधियां ली जा सकती है।

20 लाख तक के काम का प्रस्ताव

सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत व्दितीय चरण में जो ग्राम चयनित किए गए है वहां की ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद कार्यों का चिन्हांकन शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संग्रहण, खेल मैदान का निर्माण, पीडीएस दुकाने, आजीविका भवन आदि कार्यायों को प्राथमिकता दी जाए।

योजनाओं को किया प्रस्तुत

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास व्दारा योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक में सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अखिलेश पांडेय, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग जी वाय गायकवाड, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, कृषि, सहायक संचालक, मत्स्य पालन विभाग, अनुविभागीय अधिकारी वन उपस्थित रहे।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)